आर्डिनरी थी, उससे भी हम लोगों ने सेबर जेट को मार गिराया था । अभी अमेरिका पाकिस्तान को जो एफ-16 देने जा रहा है, तो जो आकाश मिसाईल-सरफेस टू एयर मिसाईल है, क्या यह एफ-16 को भी मार गिराकर फिर हिन्दुस्तान के लड़ाकू जाबांज जवानों की हैसियत को साबित करेगी कि हम पूरी तरह मजबूत हैं ।

श्री मल्लिकार्जुन : मैडम्, हम कैसे साबित करें जब तक वह आए नहीं ।

उपसभापति : क्वेश्चन नं० 345

श्री शिव कुमार मलहोत्रा : मैडम्, आपने कहा था ।

उपसभापति : मैंने कहा था, मगर हालात को देखते हुए मैं समझती हूं कि सवाल अब कोई जरूरी नहीं है ।

सैन्य कर्मियों द्वारा कार्य के समय मदिरा का सेवन

*345. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना में धूम्रपान और मद्यपान निषिद्ध है;

(ख) यदि हां, तो सेना के विक्रय केन्द्रों में मदिरा का विक्रय किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या जबलपुर स्थित आयुध निर्माणी में कार्य के समय मदिरा का सेवन किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच की जायेगी; और

(घ) क्या आयुध निर्माणियों में कर्मियों द्वारा कार्य के समय मदिरा का सेवन किये जाने की नियमित जांच की व्यवस्था की जायेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सशस्त्र सेना के कार्मिकों को ड्यूटी के दौरान मदिरापान की अनुमति नहीं है । औपचारिक परेडों अथवा सेना के वाहनों में यात्रा के दौरान धूम्रपान की अनुमति भी नहीं है । तथापि, धूम्रपान या मदिरापान सेवा संस्थानों, मैसों, आवास के क्वार्टरों, भोजन कक्षों आदि में प्रतिबंधित नहीं है । यूनिटों के कमान अफसर सैनिक शिष्टाचार और परम्पराओं के मानदंडों के अनुरूप विशेष रूप से संगठित समारोहों के दौरान धूम्रपान तथा मद्यपान की अनुमति प्रदान कर सकते हैं ।

यूनिटों द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीनें दूर-दराज के क्षेत्रों तथा विभिन्न स्थानों पर स्थित सशस्त्र सेना कार्मिकों की मदिरा संबंधी तथा अन्य बहुत-सी जरूरतें पूरी करती हैं ।

जब आयुध फैक्ट्री बोर्ड को खमरिया, जबलपुर की आयुध निर्माणी से कार्य-घंटों के दौरान मदिरापान की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी उस समय सुरक्षा स्टाफ ने वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान ड्यूटी के समय मदिरापान करने के कई मामलों का पता लगाया था । इन मामलों में समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। आयुध निर्माणियों के सुरक्षा स्टाफ द्वारा अचानक जांच की जाती है । यदि कार्य-घंटों के दौरान कोई सिविल कर्मचारी मदिरापान किए हुए पाया जाता है तो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली के अंतर्गत दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है । यदि सशस्त्र सेना का कोई कार्मिक ड्यूटी के दौरान मदिरापान कर नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सेना/वायुसेना/नौसेना के अधिनियमों तथा नियमों/विनियमों के अन्तर्गत बने संगत प्रावधानों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है ।

श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : महोदया, स्टेटमेंट के पैरा 2 के मैं दो सेंटेंस कोटकर रहा हूं :

> "यूनिटों द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीनें दूर-दराज के क्षेत्रों तथा विभिन्न स्थानों पर स्थित सशस्त्र सेना कार्मिकों की मदिरा संबंधी तथा अन्य बहुत-सी जरूरतें पूरी करती हैं ।"

तो मैडम अब प्रश्न उठता है, क्या इन कैंटीनों से सेना के अतिरिक्त अन्य बाहरी व्यक्तियों को भी शराब बेची जाती है और बेचे जाने की शिकायतें मिलने पर क्या कार्रवाई की जाएगी ?

SHRI MALLIKARJUN : Madam, it is a known fact that the Armed Forces personnel do take liquor from the military canteen. (*Interruptions*). All categories of people; down to the level of soldiers. The question is whether we should stop smoking and drinking. When they are on duty, they are prohibited from taking liquor and they are not even supposed to smoke when they are in uniform.

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : उससे मुझे संतोष है जो आपने स्टेटमेंट दिया है । मैं यह कह रहा हूं कि इन कैंटीनों द्वारा क्या सेना के अतिरिक्त बाहरी लोगों को भी शराब बेची जाती है ?

श्री मल्लिकार्जुन : बाहरी लोगों को नहीं बेची जाती है, सिर्फ सर्विंग पर्सोनल, एक्स सर्विसमैन

according to the quota, it is being issued.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Safety Norms for Private and National Carriers

*341. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government have drawn up new safety norms for both private and national carriers during the recently held meeting of DGCA, private taxi operators, Indian Airlines and Air India officials in New Delhi; and

(b) if so, the details of steps taken to enhance air worthiness standards of planes so as to ensure passengers' safety-keeping in view the recent incident, involving Damania Airways and Sahara India Airlines in Delhi?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) At the meeting with private air taxi operators, Indian Airlines and Air India convened by DGCA on 18th and 19th March, 1994, the operators were advised to take the following additional measures to enhance safety of operations:—

(i) All pilots should practise flight procedures during emergencies on simulators during refresher courses,

(ii) Overhaul life of aircraft components should be reviewed, and

(iii) Air India and Indian Airlines should establish separate quality control and quality assurance divisions in view of their large-scale operations.

(b) Steps taken to improve airworthiness standard of aircraft and safety of aircraft operations include strengthening of quality control set up, prompt rectification of snags, establishment of adequate maintenance facilities, monitoring of Digital Flight Data Recorder and Cockpit Voice Recorder readouts, pre-flight medical examination of crew, observance of special precautions while operating to/from short airfields, adherence to standard operating procedures, implementation of recommendations emanating from accident investigation reports etc.

Hike in salary of Judges of High Courts/Supreme Court

*346. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN:
SHRI MISA R. GANESAN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are contemplating a hike in the salary of Judges of High Courts and Supreme Court;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) whether it would be extended to Judges in lower judiciary like district and Session Judges?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) No, Sir.

(b) While the salary of the Judges of High Courts and Supreme Court was last revised in 1986, the admissible perquisites and allowances have been improved from time to time since 1986 keeping in view the dignity and status of the Judges.

(c) It is for the respective State Governments to consider the revision of the pay scales and other allowances of their judicial officers.

Losses to HMT

*347. SHRI S. MUTHU MANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the total amount of loss incurred by the Hindustan Machine Tools Limited (HMT) during the financial year 1992-93 and the first half of 1993-94;

(b) whether it is a fact that the loss is mainly because of stiff competition from the manufacturers of watches and lamps in the private sector;

(c) whether it is also a fact that the sales of watches and lamps of HMT have come down heavily because of more attractive watches and lamps made available by private manufacturers in the market; and

(d) if so, what are the details of corrective measures the HMT contemplate to over-come this problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) HMT incurred a net profit of Rs. 2.72 crores in 1992-93 and a provisional net loss of Rs. 75.28 crores during the first six months of 1993-94.

(b) and (c) The losses are mainly because of stiff competition, product obsolescence, high overheads, demand sluggishness and high inventories and debtors.

(d) HMT has re-organised itself into five business groups and has taken steps to reduce inventories, sundry debtors and overhead expenditure. Government has also allowed HMT in principle to convert its individual business groups into joint venture companies.